विषम परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ता और वे अपने परिवार के साथ रहकर अपने बाल-बच्चों का सही लालन-पालन करते, जिससे उस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास भी होता।

अतः माननीय महोदय जी, मैं आपके माध्यम से अपनी सरकार और राज्य सरकारों से मांग करता हूं कि उक्त क्षेत्रों में भारी उद्योग या कल-कारखाना और देशी-विदेशी निवेशकों से निवेश कराने की कृपा करें, जिससे उस क्षेत्र का विकास हो सके। ...(**समय की घंटी**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the issue raised by the hon. Member, Shri Sakaldeep Rajbhar: Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shrimati Vandana Chavan (Maharashtra), Dr. Amar Patnaik (Odisha), Prof. Manoj Kumar Jha (Bihar) and Dr. Fauzia Khan (Maharashtra).

माननीय सदस्यगण, आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप बोलें, उस पर पहले से तैयार लिखित भाषण न पढ़ें। श्री अब्दुल वहाब जी; Demand to include all *Navodaya Vidhyalaya* employees under CCS Pension Scheme.

Demand to include all Navodaya Vidyalaya employees under CCS pension scheme

SHRI ABDUL WAHAB (Kerala): Mr. Deputy Chairman, Sir, the *Navodaya Vidhyalaya* since 1985 has been there all over India. It is a wonderful experiment and it has won a lot of sidelined rural students. Nowadays, after passing out from the *Navodaya*, they are in good positions. The issue is that the teachers and the employees are not in this pension scheme. Over the last several years, this matter is being raised. Even the parliamentary committee has given its recommendation. But it is still with the Finance Department. Thousands of employees are waiting for this to happen. All other institutions are being given pension and other facilities by the Government of India. But, why is this lagging behind? That is my point. Hence, I hope that before they would come out with '*Chalo* Parliament' and Parliament blockade, please consider this one as early as possible. That is my demand. Thank you.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the issue raised by the hon. Member, Shri Abdul Wahab: Shri Abir Ranjan Biswas (West Bengal), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Dr. Kanimozhi NVN Somu (Tamil Nadu), Shri Jose K. Mani (Kerala), Dr. John Brittas (Kerala), Shri Binoy Viswam (Kerala), Shri Sandosh Kumar P. (Kerala), Dr. Santanu Sen (West Bengal), Shrimati Jebi Mather Hisham (Kerala), Shri Jayant Chaudhary (Uttar Pradesh), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shrimati Sulata Deo (Odisha), Shrimati Vandana Chavan (Maharashtra), Shri M. Mohamed Abdulla and Dr. Amar Patnaik (Odisha).

Now, Shrimati Sulata Deo; request to revise the financial assistance given under PMAY (U).

Demand to revise the financial assistance given under PMAY (U)

श्रीमती सुलता देव (ओडिशा): उपसभापति महोदय, करीब डेढ़ साल होने के बाद आज पहली बार मेरा ज़ीरो ऑवर लगा है, इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूं और बोलने की परमिशन देने के लिए भी मैं तहेदिल से आभारी हूं। महोदय, प्रधान मंत्री जी ने एक बार बोला कि सब गरीबों के सिर के ऊपर छत होनी चाहिए और PMAY की शुरुआत 2015 में हुई। 2015 में PMAY के तहत अर्बन के लिए डेढ़ लाख रुपये का प्रावधान हुआ है और रूरल के लिए-जो IAP Districts हैं, उनके लिए 1.20, यानी 1,20,000 का और जो नॉन IAP हैं, उनके लिए 1,10,000 का। 2015 में जो डेढ़ लाख था और जो 1,20,000 और 1,10,000 था। आज आठ साल के बाद सारी commodity का रेट, सारी चीज़ों का रेट बढ़ गया है। अगर सारी चीज़ों का रेट बढ़ रहा है, तो ये assistance revised होनी चाहिए। जो गरीब है, उसकी छत के लिए उसके हाथ से ज्यादा खर्चा हो रहा है, तो वह बेचारा कहां से पैसा लाएगा। मैं यह बोलना चाहती हूं कि अगर आठ साल में सीमेंट का रेट 30-40 परसेंट बढ़ा है, नॉन एग्रीकल्चर लेबर कॉस्ट भी 30 से 40 परसेंट बढ़ी है, स्टील का रेट 100 परसेंट बढ़ा है, ट्रांसपोर्टेशन का रेट बढ़ रहा है और सारी चीज़ों का रेट बढ़ रहा है। अगर देखें, तो सबका रेट बढ़ने के साथ-साथ, उसकी कॉस्ट बढ़ रही है, इसलिए कहीं न कहीं कॉस्ट भी बढ़नी चाहिए। यदि कॉस्ट नहीं बढ़ेगी, तो गरीब का घर कभी complete नहीं हो पाएगा।

महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि 330 स्क्वायर फीट के लिए कम से कम चार लाख रुपये खर्च होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को अस्सिटेंस राशि बढ़ानी चाहिए। यदि यह तीन लाख हो जाएगी, तो वह गरीब अपने लिए एक छत बना सकता है और उसमें रह सकता है।

हमारे ओडिशा में MGNREGA में 95 डेज़ की लेबर कॉस्ट ऐड की जाती है। जो जल्दी काम खत्म करते हैं - अगर दो महीने के अंदर काम खत्म करते हैं, उनको 20 हज़ार रुपये इन्सेंटिव दिया जाता है और चार महीने के अंदर काम खत्म करते हैं, उनको 10 हज़ार का इन्सेंटिव दिया जाता है।

सर, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि इस कॉस्ट को ज्यादा बढ़ाया जाए, ताकि जो गरीब लोग हैं, उनके लिए सिर के ऊपर छत बनाने के लिए, PMAY घर बनाने के लिए सहज और सरल हो। मैं यह सोच रही हूं कि मेरे जो सारे साथी सांसद हैं, वे इस बात से सहमत होंगे कि ...

श्री उपसभापतिः धन्यवाद, श्रीमती सुलता देव जी। The following hon. Members associated themselves with the matter raised by the hon. Member, Shrimati Sulata Deo: Shri Niranjan Bishi (Odisha), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shri Abir Ranjan Biswas (West Bengal), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Dr. Amar Patnaik (Odisha), Shri Kanakamedala Ravindra Kumar (Andhra Pradesh), Shrimati Vandana Chavan (Maharashtra), Shrimati Priyanka Chaturvedi (Maharashtra), Dr. Kanimozhi NVN